

पत्र सूचना कार्यालय  
भारत सरकार  
प्रधानमंत्री कार्यालय

10-जनवरी-2017 20:19 IST

वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2017 के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री का संबोधन

मैं वाइब्रेंट गुजरात समिट में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको नए साल में समृद्धि और सफलता के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे याद है कि 2003 में किस प्रकार इसकी शुरुआत हुई थी। तब से यह एक बहुत ही सफल यात्रा रही है।

मैं भागीदार देशों और संगठनों के लिए अपना व्यक्त करता हूं। इस सूची में जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस, पोलैंड, स्वीडन, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। मैं वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम के प्रारंभिक भागीदार देशों: जापान और कनाडा को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं।

कई अन्य प्रतिष्ठित वैश्विक संगठन एवं नेटवर्क भी इस आयोजन के भागीदार हैं। इस भागीदारी के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आपकी उपस्थिति यहां एकत्रित हुए कारोबारियों और युवा उद्यमियों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। आपके समर्थन के बिना इस आयोजन के आठ द्विवार्षिक अध्यायों, जो प्रत्येक बेहतर और पहले से बड़ा है, को नहीं देखा जा सकता था।

पिछले तीन आयोजन विशेष रूप से बड़े थे। 100 से अधिक देशों से राजनीतिक एवं व्यापार जगत के नेताओं की उपस्थिति और दुनियाभर से बड़ी संख्या में संगठनों की मौजूदगी ने वास्तव में इसे एक वैश्विक आयोजन बना दिया।

मैं प्रतिभागियों से आग्रह करता हूं कि वे एक-दूसरे तक पहुंचें और इस सम्मेलन का सबसे अधिक फायदा उठाएं। आपको व्यापार शो एवं प्रदर्शनी को भी देखना चाहिए जहां सैकड़ों कंपनियों ने अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया है।

गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि है जो भारत के व्यापार की भावना का भी प्रतिनिधित्व करता है। समय के साथ-साथ इसने वाणिज्य एवं उद्यम को बढ़ावा दिया। सदियों पहले यहां के लोग अवसरों की तलाश में सात समुद्र पार गए थे। आज भी यह राज्य विदेश में रहने और काम करने वाले हमारे सबसे अधिक लोगों का मूल होने का दावा करता है। और वे जहां भी गए, वहां एक मिनी-गुजरात बना दिया। हम गर्व से कहते हैं: ज्यों ज्यों बसे एक गुजराती, त्यों त्यों सदाकाल गुजरात। यानी जहां एक गुजराती रहता है, वहां हमेशा के लिए गुजरात रहता है।

गुजरात में फिलहाल पतंग महोत्सव की तैयारी चल रही है। पतंग हम सब को ऊंची उड़ान के लिए प्रेरित करे।

**मित्रों,**

जैसा कि मैंने अक्सर कहा है कि भारत की ताकत तीन डी: डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिमांड (लोकतंत्र, जनसांख्यिकी और मांग) में निहित है।

हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे लोकतंत्र की गहराई है। कुछ लोगों का कहना है कि लोकतंत्र प्रभावी और तेज शासन सुनिश्चित नहीं कर सकता। लेकिन हमने पिछले ढाई साल में देखा है कि लोकतांत्रिक ढांचे में भी त्वरित परिणाम देना संभव है।

पिछले ढाई साल के दौरान हमने राज्यों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की संस्कृति को भी उभारा है। सुशासन के मापदंडों पर राज्यों का मूल्यांकन किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में विश्व बैंक हमारी मदद कर रहा है।

जहां तक जनसांख्यिकी की बात है तो हमारा जीवंत युवाओं का देश है। भारत के अनुशासित, समर्पित और प्रतिभाशाली युवा वैश्विक स्तर पर बेजोड़ कार्यबल प्रदान करते हैं। हम दूसरे सबसे बड़े अंग्रेजी भाषी देश हैं। हमारे युवा केवल रोजगार की तलाश नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने जोखिम उठाना शुरू कर दिया है और अक्सर वे उद्यमी बनना पसंद करते हैं।

मांग के मोर्चे पर हमारे बढ़ते मध्यमवर्ग एक विशाल घरेलू बाजार प्रदान करता है।

भारतीय प्रायद्वीप जिन सागरों से घिरा है वे हमें अफ्रीका, पश्चिम एशिया और यूरोप सहित विश्व के बड़े बाजारों से जोड़ते हैं।

प्रकृति हम पर मेहरबान रहा है। हमारे तीन फसल सीजन हमें बहुतायत में भोजन, सब्जियों और फलों को उगाने में समर्थ बनाते हैं।

हमारे वनस्पतियों और जीव-जंतुओं में विविधता अद्वितीय है। हमारी संस्कृति और उसके सजीव प्रतीकों की समृद्धि अनोखी है। हमारे संस्थानों और विद्वानों को दुनियाभर में मान्यता मिली है। भारत अब एक उभरता आरएंडडी केंद्र बन चुका है। हमारे यहां विश्व की दूसरी सबसे बड़ी संख्या में वैज्ञानिक और इंजीनियर पैदा होते हैं।

हमारा मनोरंजन उद्योग दुनियाभर में लहर पैदा कर रहा है। इन सब से अपेक्षाकृत कम लागत पर बेहतर जीवन सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।

**मित्रों,**

हमारी सरकार स्वच्छ शासन मुहैया कराने और भ्रष्टाचार एवं भाई-भतीजेवाद की प्रचलित व्यवस्था को खत्म करने के वादे के साथ चुनी गई थी। इसलिए नीतियों और अर्थव्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाना हमारा सपना और मिशन है। हमने उस दिशा में कई कदम उठाए हैं और निर्णय लिए हैं। इसके कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ:

हम बदलाव ला रहे हैं:

- संबंध आधारित शासन से प्रणाली आधारित शासन में;
- विवेकाधीन प्रशासन से नीति आधारित प्रशासन में;
- अव्यवस्थित हस्तक्षेप से तकनीकी हस्तक्षेप में;
- पक्षपात से समान अवसर मुहैया कराने में;
- अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से औपचारिक अर्थव्यवस्था में।

इसे करने में डिजिटल प्रौद्योगिकी ने अहम भूमिका निभाई है। मैं अक्सर कहता हूँ कि ई-शासन कहीं अधिक आसान और प्रभावी शासन होता है। मैंने नीतियों से संचालित शासन की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। ऑनलाइन प्रक्रियाओं से निर्णय लेने में खुलापन और तेजी लाने में मदद मिलती है। इस लिहाज से हम अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिए काम कर रहे हैं ताकि पारदर्शिता लाई जा सके और चालाकी को खत्म किया जा सके। विश्वास कीजिए, हम दुनिया की सबसे डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने की दहलीज पर हैं। आप में से अधिकतर भारत में यह बदलाव देखना चाहते थे। मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि यह आपके सामने हो रहा है।

पिछले ढाई साल के दौरान हमने भारत की क्षमता को पहचानने और अर्थव्यवस्था की सही राह सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम किया है। उसके परिणाम उत्साहजनक रहे हैं। जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा, चालू खाते का घाटा और विदेशी निवेश जैसे प्रमुख वृहत आर्थिक संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार दिख रहे हैं।

भारत दुनिया में सबसे तेजी से उभरने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है। वैश्विक मंदी के बावजूद हमने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। भारत आज वैश्विक अर्थव्यवस्था का चमकता सितारा है। हमें वैश्विक वृद्धि को गति देने वाले इंजन के रूप में देखा जा रहा है।

विश्व बैंक, आईएमएफ एवं अन्य संस्थानों ने आने वाले दिनों में बेहतर वृद्धि का अनुमान लगाया है। साल 2014-15 में भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में 12.5 प्रतिशत का योगदान किया। वैश्विक वृद्धि में इसका योगदान वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी के मुकाबले 68 प्रतिशत अधिक है।

व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना और निवेश आकर्षित करना मेरी पहली प्राथमिकता है। हमें अपने युवाओं के लिए अवसर पैदा करने के लिहाज से ऐसा करना होगा। इस जज्बे के साथ हम कुछ ऐतिहासिक पहल के कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसमें वस्तु एवं सेवाकर शामिल है।

दिवालिया एवं दिवालियापन संहिता, नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नया मध्यस्थता ढांचा और नई आईपीआर व्यवस्था तैयार हैं। नए वाणिज्यिक न्यायालय भी स्थापित किए जा रहे हैं। ये महज कुछ उदाहरण हैं कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरी सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार जारी रखने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है।

**मित्रों,**

हमने कारोबारी सुगमता पर सबसे अधिक जोर दिया है। हमने लाइसेंसिंग प्रक्रिया को आसान बनाने और मंजूरी, रिटर्न एवं निगरानी संबंधी प्रक्रियाओं एवं प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं। हम नियामकीय ढांचे में सुधार के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में सौकड़ों कार्य बिंदुओं के कार्यान्वयन की निगरानी कर रहे हैं। यह सुशासन के हमारे वादे का हिस्सा है।

हमारे प्रयासों के परिणाम विभिन्न संकेतकों पर भारत की वैश्विक रैंकिंग में साफ झलकते हैं। पिछले दो साल के दौरान तमाम वैश्विक आकलन और रिपोर्टों से पता चलता है कि भारत ने अपनी नीतियों कार्य प्रणालियों और आर्थिक स्थिति में सुधार किया है।

विश्व बैंक की इंडिंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यूएनसीटीएडी की ओर से जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2016 में भारत 2016-18 के लिए शीर्ष संभावित मेजबान अर्थव्यवस्थाओं की सूची में तीसरे पायदान पर है।

विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट 2015-16 और 2016-17 में भी हमारी रैंकिंग में 32 पायदानों का सुधार हुआ है। डब्ल्यूआईपीओ एवं अन्य संस्थानों द्वारा तैयार वैश्विक नवाचार सूचकांक 2016 में हम 16 पायदान ऊपर पहुंच चुके हैं। हम विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2016 में 19 पायदान चढ़ चुके हैं।

आप देख सकते हैं कि हम सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं के करीब जा रहे हैं। दिन-ब-दिन हम दुनिया के साथ अधिक से अधिक एकीकृत हो रहे हैं। हमारी नीतियों एवं प्रथाओं के सकारात्मक प्रभाव से हमारा विश्वास बढ़ा है। इससे हमें व्यापार करने के लिहाज से सबसे आसान जगह बनने के लिए अपनी प्रक्रियाओं को और अधिक सरल बनाने के लिए प्रेरणा मिली है।

हम कारोबार स्थापित करने और उसके फलने-फूलने के लिए हर रोज हमारी नीतियों एवं प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बना रहे हैं। हमने हमारी एफडीआई नीति को कई क्षेत्रों में और कई तरीके से उदार बनाया है। भारत आज सबसे अधिक खुली अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है।

माहौल में इस बदलाव को घरेलू और विदेशी दोनों निवेशक मान रहे हैं। देश में अब एक उत्साहजनक स्टार्टअप इकोसिस्टम आकार ले रहा है। युवा शक्ति का यह प्रदर्शन खुशी की बात है।

पिछले ढाई साल के दौरान कुल एफडीआई प्रवाह एक सौ तीस अरब अमेरिकी डॉलर को छू गया है। पिछले दो वित्त वर्ष के दौरान एफडीआई इक्विटी प्रवाह इससे पिछले दो वित्त वर्ष के मुकाबले साठ प्रतिशत अधिक रहा। वास्तव में पिछले साल देश में आने वाला कुल एफडीआई निवेश अब तक का सर्वाधिक रहा।

हम जिन देशों से एफडीआई प्राप्त कर रहे हैं और जिन क्षेत्रों में एफडीआई निवेश किया जा रहा है, उनकी संख्या में भी पिछले दो साल के दौरान काफी विविधता आई है। भारत अब एशिया प्रशांत क्षेत्र में पूंजी निवेश हासिल करने वाला प्रमुख देश बन चुका है। एफडीआई निवेश प्रवाह के लिहाज से भी यह विश्व के दस शीर्ष देशों में लगातार बरकरार है।

लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती। निवेश पर रिटर्न मुहैया कराने के लिहाज से भी भारत ने दूसरे देशों को पीछे छोड़ दिया है। साल 2015 में भारत बेसलाइन प्रॉफिटैबिलिटी इंडेक्स में पहले स्थान पर पहुंच गया।

### मित्रों,

मेक इन इंडिया भारत का अब तक का सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका है। यह भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र बनने के लिए निर्देशित है।

मैं साथियों यह अनुभव करता हूं, मैं दुनिया में जहां-जहां गया, मैं अगर पांच बार मेक इन इंडिया बोलता था तो वहां मेजबान देश के नेता 50 बार मेक इन इंडिया बोलते थे। एक प्रकार से मेक इन इंडिया, यह दुनिया की नजरों में भारत को एक निवेश की जगह बना चुका है। भारत में राज्यों की पहल, केंद्र सरकार के सहयोग, यह संयुक्त प्रयास मेक इन इंडिया के लिए बहुत सारे द्वार खोल चुका है।

इस अवसर का लाभ हिंदुस्तान के राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा हो, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो और वह भी अच्छा शासन एवं माहौल के आधार पर हो। प्रतिस्पर्धा पहले भी हुआ करती थी, 15 साल पहले एक राज्य दूसरे से ज्यादा चीजें दे देता था, दूसरे तीसरे से ज्यादा देता था, देने की स्पर्धा होती थी। आखिर अगर कोई नहीं आता था लेकिन जहां-जहां अच्छे शासन को बल दिया गया, जहां-जहां उचित माहौल पैदा किया गया, जहां-जहां कानूनों को ठीक किया गया, जहां-जहां कारोबारी माहौल को दोस्ताना बनाया गया, वहां पर अधिक मात्रा में दुनिया के बाहर के लोग भी आने लगे और इसलिए मेक इन इंडिया या दुनिया में कहीं पर भी समझाना पड़े ऐसी स्थिति नहीं है। और मैं गुजरात सरकार को अभिनंदन करता हूं। उन्होंने अपनी प्रगतिशील नीतियों के आधार पर अच्छे शासन को बल देते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में बहुत ही अग्रिमता सिद्ध की है। गुजरात सरकार की पूरी टीम को इसके लिए मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

मेक इन इंडिया ने हाल में अपना दूसरा वर्षगांठ मनाया है।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा विनिर्माण देश बन चुका है जबकि पहले वह नौवें पायदान पर था। विनिर्माण में हमारे सकल मूल्यवर्द्धन में 2015-16 के दौरान 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह पिछले तीन वर्षों के दौरान पांच से छह प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले काफी अधिक है।

इन सबसे हमें रोजगार बाजार का विस्तार करने और हमारे लोगों की क्रयशक्ति बढ़ाने में मदद मिलती है। लेकिन अंतरनिहित शक्ति इससे कहीं ज्यादा है।

आपको कुछ उदाहरण देते हैं: भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में अगले दस साल में करीब पांच गुना वृद्धि होने का अनुमान है। इसी प्रकार, भारत में वाहनों की पहुंच कम होने के कारण यह विश्व के सबसे आकर्षक वाहन बाजारों में शुमार है।

सरकार के स्तर पर हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारी विकास प्रक्रिया समावेशी है और वह ग्रामीण एवं शहरी दोनों समुदायों को गले लगाती है।

भारत एक ऐसा देश है जहां हम गांव और शहर के बीच संतुलित विकास के पक्ष में हैं। हमारी नीतियों का लाभ गांव और शहर दोनों को समान रूप से मिलना चाहिए। और इसलिए हमारी योजना की प्राथमिकता में भी गांव को भी उतना ही महत्व मिले, हर विकास की यात्रा का अंतिम लाभ गांव के गरीब किसान तक पहुंचे, यह हमारी प्राथमिकता रहने के कारण सारी नीतियों के केंद्र में उन बातों को हमने बल दिया है।

हम भारत के लिए प्रतिबद्ध हैं कि यहां:

- रोजगार की बेहतर संभावनाएं हों;
- बेहतर आय हो;
- बेहतर क्रयशक्ति हो;
- बेहतर जीवन हो;
- और बेहतर रहन-सहन हो।

**मित्रों,**

हमारी विकास जरूरतें काफी बड़ी हैं। हमारा विकास कार्यक्रम महत्वाकांक्षी है। उदाहरण के लिए:

-हम हरेक सिर के ऊपर छत मुहैया कराना चाहते हैं।  
गरीब को घर होना चाहिए और अपना घर होना चाहिए और 2022 तक होना चाहिए, यह सपना लेकर हम चल रहे हैं।

-हम हरेक हाथ को रोजगार देना चाहते हैं।  
देश में 80 करोड़ लोग 35 वर्ष से कम आयु वर्ग के हैं जो एक प्रकार से युवा भारत है। 80 करोड़ युवा जिनकी उम्र 35 वर्ष से कम है, इन हाथों में हुनर हो, काम का अवसर हो, तो नया हिंदुस्तान हमारी आंखों के सामने बना करके खड़ा कर देंगे। यह विश्वास हिंदुस्तान के नौजवानों के प्रति मेरा है, हम सबका हैं और हम सब की जिम्मेदारी भी है कि उस अवसर को हम दें। और हम अवसर दे सकते हैं, संभावनाएं भरपूर पड़ी हैं।

- हम स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करना चाहते हैं;
- हम तेजी से सड़क और रेलवे का निर्माण करना चाहते हैं;
- हम हरियाली बरकरार रखते हुए खनिजों का उत्खनन करना चाहते हैं;
- हम दमदार शहरी सुविधाओं का निर्माण करना चाहते हैं;
- हम अपने जीवन की गुणवत्ता को बेहतर से बेहतर होते देखना चाहते हैं।

हम अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे: प्रमुख एवं सामाजिक दोनों क्षेत्रों में; शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में; की ओर छलांग लगा रहे हैं। इसमें फ्रंट कॉरिडोर, औद्योगिक कॉरिडोर, हाई स्पीड एवं मेट्रो रेल परियोजनाएं, लॉजिस्टिक्स पार्क, स्मार्ट सिटी, तटीय क्षेत्र, क्षेत्रीय हवाई अड्डे, जल, साफ-सफाई एवं ऊर्जा संबंधी गतिविधियां शामिल हैं। हमारी प्रति व्यक्ति बिजली खपत निश्चित तौर पर बढ़नी चाहिए। यहां तक कि ऐसा करते समय हम अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

हम पर्यटन को व्यापक पैमाने पर प्रोत्साहित करना चाहते हैं और इसके लिए पर्यटन बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है।

जब मैं अक्षय ऊर्जा की बात करता हूं 175 गीगावॉट; एक जमाना था जब हम मेगावॉट की चर्चा करते भी डरते थे। आज देश गीगावॉट के सपने देख रहा है। यह बहुत बड़ा बदलाव है। 175 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा, मिश्रित ऊर्जा जिसमें सौर हो, पवन हो, नाभिकीय हो और दुनिया जो ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है, उस विश्व को बचाने का सपना हमने भी देखा है। और हम भी 175 गीगावॉट के योगदान से विश्व को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के उस संकल्प को पूरा करने में हिंदुस्तान अपनी नंबर एक की भूमिका अदा करने के लिए कृतसंकल्प होकर आगे बढ़ रहा है। तो मैं पूरे विश्व को निमंत्रण देता हूं कि आइये 175 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के लिए अपार संभावनाएं हैं और हमारी नीतियां काफी प्रगतिशील हैं। मुझे विश्वास है कि यह मानवता का भी काम है; जीवन की तरफ देखने का एक दृष्टिकोण बदलने का यह अवसर है। हमने दो शताब्दियों को प्रकृति के शोषण में खपा दी है। अब हमारा दायित्व है कि आने वाली शताब्दियों को प्रकृति के शोषण के हमारे सोच में से बाहर लाकर हमारी प्रकृति को मजबूत करने की बुनियादी चीजों को लेकर चलना इसका अवसर है। और उस बात को लेकर हम चलेंगे तो हम अवश्य ही विश्व में एक बड़े परिवर्तन की संभावनाओं में बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा कर सकते हैं।

सड़कों के निर्माण और रेलवे लाइन बिछाने के लिए हमारे लक्ष्यों में कई गुना वृद्धि हुई है। भारत विश्व के सबसे बड़े निर्माण बाजार के रूप में उभरने जा रहा है क्योंकि यहां लाखों मकान बनाए जाने हैं। इन सबसे निवेशक समुदाय के लिए अप्रत्याशित संभावनाएं पैदा हो रही हैं। आप लोगों में से अधिकतर हमारे साथ जिन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं उनमें शामिल हैं:

- हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक;

-सॉफ्टस्किल से लेकर वैज्ञानिक स्वभाव तक;  
-रक्षा प्रणाली से लेकर साइबर सुरक्षा तक;  
-औषधि से लेकर पर्यटन तक।

मैं दृढ़ता के साथ कह सकता हूँ कि भारत अकेले पूरे महाद्वीप के प्रतिस्पर्धियों के बराबर अवसर पैदा कर सकता है। आज यह पूरी सदी की संभावनाएं प्रदान कर रहा है। और मैं चाहता हूँ कि यह सब स्वच्छ, हरित और स्थायी तरीके से हो। हम पर्यावरण की रक्षा करने और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी बरकरार रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कुल मिलाकर सदियों से भारत का यही रुख रहा है।

भारत में आपका स्वागत है:

-यह परंपरा और शांति की भूमि है;  
-यह सहानुभूति और उत्साह की भूमि है;  
-यह प्रयोग और उद्यम की भूमि है;  
-उद्घाटन और अवसरों की भूमि है।

मैं एकबार फिर आपका स्वागत करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ कि आप:  
-आज के भारत;  
-और कल के भारत का हिस्सा बनें।

मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आवश्यकता पड़ने पर कभी भी मैं आपका हाथ थामने के लिए उपलब्ध रहूंगा।

धन्यवाद।

\*\*\*\*\*

**AKT/AK/SKC**



**पत्र सूचना कार्यालय  
भारत सरकार  
प्रधानमंत्री कार्यालय**

01-फरवरी-2017 16:50 IST

**प्रधानमंत्री का बजट 2017-18 पर वक्तव्य**

हमारे देश के वित्तमंत्री अरुण जेटली जी को उत्तम बजट देने के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। ये एक ऐसा बजट है जो गरीब को सशक्त बनाएगा बुनियादी ढाँचे को और मजबूत भी बनाएगा, गति भी देगा हर किसी की उम्मीदों को अवसर देगा, अर्थ तंत्र को एक नई ताकत देगा, नई मजबूती देगा और विकास को बहुत तेजी देगा। इस बजट में हाइवे भी बने आइवे भी बढे, दाल के दाम से लेकर Data की स्पीड तक, रेलवे के Modernization से लेकर के सरल economic निर्माण करने की दिशा में, शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य तक, उद्यमी से लेकर उद्योग तक, Textile manufacturing से लेकर के Tax deduction तक हर किसी के सपने को साकार करने का ठोस कदम इस बजट में साफ-साफ नजर आता है। इस ऐतिहासिक बजट के लिए वित्तमंत्री के साथ- साथ उनकी पूरी टीम भी अभिनंदन के अधिकारी हैं।

ये बजट देश के विकास के लिए पिछले ढाई वर्ष में जो कदम उठाए गए, जो फैसले लिए गए और भविष्य में और मजबूती के साथ आगे बढ़ने के इरादों के बीच ये एक बहुत महत्त्वपूर्ण कड़ी है। इस बजट को मैं देख रहा हूँ, एक अन्य महत्त्वपूर्ण कदम है कि रेलवे बजट को General Budget में merge कर दिया गया है। इससे पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर उसको Integrated planning में मदद मिलेगी।

देश में परिवहन से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति में रेलवे अब अपना योगदान और बेहतरीन तरीके से कर पाएगी। ये बजट कृषि क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, सामाजिक कल्याण, Infrastructure इन सभी क्षेत्रों में एक विशेष ध्यान आकर्षित करता है। निवेश बढ़ाने और रोजगार के नये अवसर पैदा करने की दृष्टि से सरकार की जो प्रतिबद्धता है वह इस बजट में साफ-साफ नजर आती है। इन योजनाओं के लिए आवंटन में भी बहुत बढ़ोत्तरी की गयी है, सरकारी निवेश को मजबूती देने के लिए रोड और रेल सेक्टर के लिए भी आवंटन में काफी वृद्धि की गयी है। सरकार का लक्ष्य 2022 तक हमारे देश के किसानों की आय डबल करने का इरादा है, दोगुना करना है नीतियों एवं योजनाएं उसी प्रकार से तय की गयी हैं, बजट में सबसे ज्यादा जोर इस बार भी किसान, गाँव, गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित उनपर केंद्रित किया है।

Agriculture, Animal husbandry, Dairy, fisheries, watershed development, स्वच्छ भारत मिशन ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो गाँव की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव भी लाएंगे और ग्रामीण जीवन जीने वाले लोगों के Quality of life में भी बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। बजट में रोजगार बढ़ाने पर भी भर पूरा जोश दिया गया है नौकरी के लिए नए- नए अवसर पैदा करने वाले सेक्टर Electronic manufacturing, Textile उसको विशेष राशि दी गयी है, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को, संगठित क्षेत्र में लाने के लिए भी व्यापक प्रावधान किए गए हैं। Skill development बजट में काफी बढ़ोत्तरी की गयी है ये हमारे देश के युवाओं को ध्यान में रख करके और जो Demographic dividend है इसका भरपूर फायदा भारत को मिले उस पर ध्यान केंद्रित किया है।

महात्मा गांधी नेशनल रुरल गॉरेटी स्कीम उसके लिए भी अब तक जितना हुआ है किसी भी वर्ष में न हुआ हो इतना रिकार्ड आवंटन किया गया है। बजट में महिला कल्याण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, महिलाओं और बच्चों से जुड़ी योजनाओं के लिए बजट में वृद्धि की गयी है, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा के लिए भी बजट में काफी बढ़ोत्तरी की गयी है। आर्थिक विकास में तेजी लाने और रोजगार के नए अवसर बनाने में Housing और construction Sector इसकी बहुत बड़ी भूमिका है ये बजट ग्रामीण के साथ- साथ शहरी इलाकों में भी Housing Sector को मजबूती प्रदान करने वाला है। रेलवे के बजट में एक बात पर विशेष बल दिया है और वो है रेलवे सेफ्टी फंड इस फंड की मदद से रेलवे सुरक्षा पर पर्याप्त धन - राशि खर्च करने में मदद मिलेगी। बजट में रेलवे और रोड Infrastructure, Capital expenditure में काफी बढ़ोत्तरी कर दी गयी है।

Digital Economy के लिए जो comprehensive package दिया गया है उससे टैक्स चोरी की संभावनाएं कम होंगी और अर्थ व्यवस्था में काले धन के प्रवाह पर नियंत्रण संभव होगा। Digital Economy को एक मिशन के तौर पर शुरू किए जाने से आने वाले वर्ष में 2017-18 में दो हजार पांच सौ करोड़ Digital transaction के बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। हमारे वित्तमंत्री जी ने कर प्रणाली में जो सुधार और संशोधन किए हैं उससे मध्यम वर्ग को राहत



मिलेगी उद्योगों की स्थापना होगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे, भेद-भाव के अवसर खत्म होंगे और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

बजट में वैयक्तिक Income Tax कम करने की घोषणा देश के मध्यम वर्ग को ज्यादा स्पर्श करती है, बड़ी महत्वपूर्ण है। 10 प्रतिशत से एकदम 5 प्रतिशत कर देना बड़ा साहसपूर्ण निर्णय है। करीब-करीब हिन्दुस्तान के अधिकतम कर दाताओं को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। आपने देखा होगा बजट में कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई निरंतर चल रही है। Political Funding की चर्चा हमारे देश में बहुत होती रही है, राजनीतिक दल हमेशा चर्चा के घेरे में रहे हैं, चुनाव के अंदर Donation एकत्र करने की नयी योजना भी वित्तमंत्री जी ने देश की आशा और आकांक्षा और काले धन के खिलाफ अपनी लड़ाई के अनुरूप प्रस्तुत की है। देश के छोटे और मध्यम उद्योग नौकरी के नए अवसर पैदा करने के सबसे बड़े स्रोत हैं। इन उद्योगों की पुरानी माँग रही है कि Global competition में वैश्विक स्तर पर मुकाबला करने में उनको कठिनाइयाँ आ रही हैं। अगर इसके लिए टैक्स कम किया जाए तो हमारे लघु उद्योग जो कि करीब-करीब 90 प्रतिशत से ज्यादा हैं, देश में और इसलिए सरकार ने छोटे-छोटे उद्योगों को और उसमें परिभाषा में बदलाव करके उनके दायरे को भी बढ़ाया है और टैक्स को भी 30 प्रतिशत से घटा करके 25 प्रतिशत कर दिया है। यानि देश के उद्योग जगत के 90 प्रतिशत से ज्यादा लोग इसका लाभ ले पाएंगे। ये फैसला मुझे विश्वास है कि देश के छोटे उद्योगों को Globally competitive बनने में बहुत बड़ी मदद करेगा।

ये बजट देश के विकास के लिए एक मजबूत कदम है इस बजट से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे संपूर्ण आर्थिक विकास में मदद मिलेगी किसानों की आमदनी बढ़ाने में ये पूरक होगा। नागरिकों को उनकी Quality of life को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास ये सारी चीजों में अति अच्छी सुविधा की संभावना बढ़ेगी और बिना वित्तीय घाटा बढ़ाए देश के मध्यम वर्ग के पास उसकी खरीद शक्ति बढ़े उसके जेब में ज्यादा पैसे आएंगे। उस दिशा में प्रयास है, एक प्रकार से ये बजट हमारा देश जो बदल रहा है उसको और अधिक तेजी से बदलने का प्रयास एक प्रकार से हमारे स्वपनों से जुड़ा हुआ, हमारे संकल्पों से जुड़ा हुआ, ये बजट एक प्रकार से हमारा Future है। हमारी नयी पीढ़ी का Future है, हमारे किसान का Future है और जब मैं Future कहता हूँ तब उसका मेरे मन में एक meaning है। F से Farmers किसानों के लिए; U से underprivileged दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, महिला उनके लिए; T से Transparency पारदर्शिता Technology का Up gradation, आधुनिक भारत बनाने का स्वपना; U से Urban Rejuvenation शहरी विकास के लिए; और R से Rural Development ग्रामीण विकास के लिए; और E से नौजवानों के लिए Employment उद्योग साहसियों के लिए Internship, Enhancement नए रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नौजवान उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए मैं इस बजट के लिए इस Future को प्रस्तुत करते हुए वित्तमंत्री जी को फिर से एक बार बधाई देता हूँ, और देशवासियों को उनके स्वपने साकार करने की दिशा में ये बजट एक बहुत बड़ी सहाय व्यवस्था है जो देश को आगे भी बढ़ाएगा। विकास की नयी ऊँचाइयों को पार करेगा और देश में एक नया विश्वास का महौल बनाने में ये बजट बहुत ही उपकारक होगा। ऐसा मेरा पूरा विश्वास है, फिर एक बार वित्तमंत्री को, वित्त मंत्रालय को उनकी पूरी टीम को हृदय से बहुत-बहुत बधाई।

\*\*\*

अतुल कुमार तिवारी/ शहबाज हसीबी/ सतीश भान प्रजापति

**पत्र सूचना कार्यालय  
भारत सरकार  
प्रधानमंत्री कार्यालय**

09-मार्च-2017 11:07 IST

**संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मीडिया को सम्बोधन का मूलपाठ**

स्वागत है साथियों आप सबका।

संसद सत्र में बीच के एकविराम के बाद फिर से सब लोग एक बार बैठे हैं। प्रमुखता से बजट की बारीकी से चर्चा होगी। मुझे विश्वास है कि संवाद का स्तर, चर्चा का स्तर बहुत ही ऊपर जाएगा। देश के गरीबों के लिए काम आने वाली बातों पर ध्यान केंद्रित करने वाला संवाद होगा। हमारी यह भी आशा है कि जीएसटी में भी एक ब्रेक थू हो और होने की संभावना का कारण यह भी है कि सभी राज्यों का बहुत ही सकारात्मक सहयोग रहा है। सभी राजनीतिक दलों का भी बहुत सकारात्मक सहयोग रहा है। लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक चर्चाएं करते-करते कुछ नतीजों पर सहमति से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके कारण जीएसटी इस सत्र में पूर्ण हो जाए, उस दिशा में भी प्रयास है और सबका सहयोग रहेगा। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

\*\*\*

AKT/VK

**पत्र सूचना कार्यालय  
भारत सरकार  
प्रधानमंत्री कार्यालय**

30-जून-2017 17:40 IST

**टेक्सटाइल इंडिया 2017 के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री के भाषण का मूल पाठ**

टेक्सटाइल इंडिया 2017 में आप सभी का स्वागत है। टेक्सटाइल सेक्टर में ये अब तक का देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम है जिसमें दुनिया के 100 से ज्यादा देशों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। मैं टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, इस कार्यक्रम के आयोजकों, इसमें हिस्सा लेने आए उद्यमियों, कारीगरों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं।

मुझे खुशी है कि पहली बार केंद्र और देश की अलग-अलग राज्य सरकारें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े लोग एकजुट हुए हैं और इस मेगा इंटरनेशनल इवेंट के जरिए पूरी दुनिया को भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री की संभावना दिखा रहे हैं।

टेक्सटाइल एक ऐसा क्षेत्र है जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच एक अद्भुत bridge की तरह काम करता है। कपास की खेती हो, सिल्क का उत्पादन हो, इनका end product बहुत कुछ टेक्सटाइल सेक्टर पर निर्भर करता है। किसानों की मेहनत से उपजे raw material को बाजार मुहैया कराने का काम टेक्सटाइल सेक्टर करता है। यानि एक तरह से टेक्सटाइल agro और industry दोनों का ही part है।

भारत के इतिहास में अगर किसी एक इंडस्ट्री का हमेशा महत्व रहा है, तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही है। हजारों वर्ष पूर्व के भारतीय शास्त्रों में वस्त्रों की महिमा का जिक्र होता रहा है। सैकड़ों वर्ष पहले से ये इंडस्ट्री दूसरे देशों के साथ व्यापार का मुख्य आधार रही है। जिन रास्तों से कपड़ों और धागों को दूसरे देश ले जाया जाता था, उन रास्तों के नाम भी किसी ना किसी धागे के नाम पर प्रचलित हो गए थे। इन रास्तों से कितने ही विदेशी दार्शनिक भारत को समझने के लिए यहां आए और भारतीय संस्कृति की महानता का दर्शन करके लौटे। अपने साहित्य में भी उन्होंने भारतीय वस्त्रों और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ताकत को प्रमुखता से जगह दी।

अलग-अलग Time period में हमारे देश के साहित्य में भी इसकी छाप नजर आती रही है। करीब डेढ़ साल पहले चेन्नई में जब पहली बार नेशनल हैंडलूम डे का समारोह हुआ था, उस समय मुझे बनारस के एक बुनकर भाई ने एक Stole दिया था। इसमें कबीरदास जी का एक प्रसिद्ध दोहा हाथ से काढ़ा हुआ था। उस दोहे की कुछ पंक्तियां हैं-

**झीनी झीनी बिनी चदरिया  
काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से बिनी चदरिया।**

कबीर जो खुद सूत कातते थे, कपड़ा बुनते थे, कपड़ा रंगते भी थे। उन्होंने अपने न केवल काम में जीवन की सच्चाई को तलाशा और उसी से शब्द लेकर अपने दोहों में व्यक्त भी किया।

साथियों, वस्त्र हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता से भी जुड़े रहे हैं। या कह सकते हैं कि वस्त्र हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक रहे हैं। कितने ही शहरों और क्षेत्रों की पहचान वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही है। कांचीपुरम, बनारस या असम का सिल्क हो, कश्मीर का पश्मीना और जामावर का काम हो, बंगाल की मुस्लिम हो, लखनऊ में चिकन का काम हो, ओडिशा और तेलंगाना में हाथ से बुना हुआ इक्कत हो, गुजरात में पटोला हो, ये सैकड़ों वर्षों से अपने-अपने इलाके को पहचान देते रहे हैं। ऐसी विविधता आपको दुनिया में किसी और देश में नहीं मिलेगी।

देवियों और सज्जनों,

वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का उल्लेख आज एक bright spot के रूप में किया जाता है। यह एक अति आकर्षक वैश्विक निवेश destinations के रूप में उभर कर आया है। यह अनेक स्थायी पहलों से संभव हुआ है।

व्यापार में सहजता प्रदान करने हेतु सात हजार से भी अधिक सुधारों को कार्यान्वित किया गया। प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। सरकार ने बारह सौ से अधिक के पुराने कानूनों को समाप्त किया है। ये तो कुछ ही उदाहरण हैं।

परिणामस्वरूप, विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत ने ऊपरी छलांग लगाते हुए पिछले दो वर्षों में बत्तीस देशों का पीछे छोड़ दिया है। इस प्रकार की छलांग किसी देश ने नहीं लगाई है। भारत ने विश्व बैंक लॉजिस्टिक निष्पादन सूचकांक 2016 में उन्नीस देशों को पीछे कर दिया है। हम वर्ष 2016 में वर्ल्ड इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में भी सोलह देशों से आगे निकले हैं। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा सूचीबद्ध किए गए दस शीर्ष एफडीआई राष्ट्रों में, हम तीसरे नंबर पर हैं।

“मेक इन इंडिया” पहल के आधार पर, हमने रोजगार, उत्पादन और निर्यातों को बढ़ाने के लिए ‘स्क्ल, स्केल, स्पीड’ और ‘जीरो डिफेक्ट’, जीरो-इफेक्ट के मंत्र फूके हैं।

हमारे पास कपड़ा और परिधान सेक्टर में विदेशी निवेश के लिए अति उदारवादी निवेश नीतियां हैं।

हमने टेक्सटाइल और अपरेल सेक्टर में आटोमेटिक रूट के जरिए 100 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी है।

देवियों और सज्जनों,

कपड़ा उद्योग ने भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाई है। मूल्य श्रृंखला के मामले में यह मजबूत और प्रतिस्पर्धात्मक है। भारत कच्ची सामग्री, जैसे कि कपास, ऊन, रेशम, जूट तथा मानव-निर्मित फाइबर की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करता है। वास्तव में, कपास और जूट के मामले में भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और रेशम एवं मानव-निर्मित फाइबर में मामले में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इससे हमें बैकवर्ड इंटीग्रेशन का विशेष लाभ मिलता है, जो कि शायद अन्य देशों के पास नहीं है। इसके अलावा, भारत के पास spinning, weaving, knitting और apparel की मजबूत मैन्युफैक्चरिंग क्षमताएं हैं। हमारे पास किफायती लागत पर युवा श्रमिक उपलब्ध हैं।

उच्च आर्थिक वृद्धि से हमारी आय और उसे खर्च करने की क्षमता बढ़ी है। इसके परिणामस्वरूप, कपड़ा उत्पादों की घरेलू बाजार में ऊंची मांग होती है। हमारा देश युवाओं की आकांक्षाओं का देश है, जो कपड़ा, परिधान और हस्त निर्मित लाइफस्टाइल उत्पादों पर बेहिक खर्च करते हैं। अपरेल और लाइफस्टाइल उत्पादों के लिए घरेलू बाजार का वर्तमान आकलन 85 बिलियन US Dollars किया गया है, जिसकी वर्ष 2025 तक बढ़कर 160 बिलियन US Dollars होने का अनुमान है। इस मांग का आधार हमारा बढ़ता मध्यम वर्ग होगा।

देश में विनिर्मित textiles और apparel के लिए वैश्विक मांग भी काफी है। भारत textiles का निर्यात करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है, और भारत का वैश्विक अंश लगभग 5 प्रतिशत है। पारंपरिक हथकरघा और हथकरघा उत्पादों सहित भारतीय textiles का निर्यात 100 से भी अधिक देशों को किया जाता है। कभी-कभी भारतीय पर्यटक यह महसूस कराने के लिए कि चूंकि textiles भारत में विनिर्मित किए गए हैं, इसलिए वे विदेश में भी भारतीय textiles खरीदते हैं।

Textiles सेक्टर रोजगार के काफी अवसर मुहैया कराता है। कृषि के बाद आज यह हमारा दूसरा सबसे बड़ा employer है। 45 मिलियन से अधिक लोग सीधे इस सेक्टर में employed हैं और 60 मिलियन से अधिक लोग इससे जुड़े कार्यों में employed हैं।

इसी को ध्यान में रखते हुए इस सरकार में टेक्सटाइल सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पिछले वर्ष एक टेक्सटाइल Package दिया गया है। जिसके तहत apparel और made-up sector को मजबूती दी जा रही है।

सरकार ने तय किया है कि Apparel और Made-up सेक्टर में जो भी कंपनी या कारोबारी नए श्रमिकों को रोजगार देते हैं उन्हें आर्थिक मदद दी जाएगी। लेकिन आर्थिक मदद का तरीका ये होगा कि वो जिस भी कर्मचारी को रखेंगे, उनके Employee Provident Fund में कंपनी की तरफ से जो 12 प्रतिशत राशि दी जाती है, उसे सरकार खुद वहन करेगी। इसका फायदा ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा श्रमिक formal सेक्टर में शामिल होंगे।

इसके अलावा सरकार ने Apparel सेक्टर में fixed term employment का भी रास्ता खोला है। यानि ये श्रमिक एक specific time period के लिए नियुक्त होंगे लेकिन इस दौरान उन्हें वही सुविधाएं मिलेंगी तो किसी परमानेंट कर्मचारी को मिलती हैं। इससे भी श्रमिकों की स्थिति में सुधार आएगा।

इनकम टैक्स एक्ट के तहत भी इस सेक्टर की कंपनियों को छूट दी गई है। ऐसी मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स जहां कम से कम 100 श्रमिक हैं, वो किसी नए श्रमिक को 150 दिन तक रोजगार देती हैं तो भी उन्हें टैक्स में राहत दी जा रही है।

देवियों और सज्जनों,

कौशलयुक्त मानवशक्ति में बड़े अंतराल को भरने के लिए industry-oriented प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए एक इंटीग्रेटेड स्किल डिवलपमेंट स्कीम का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है।

मैन्यूफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में हमारी मजबूती का आधार हमारी विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और अनुसंधानिक संस्थानों को विकसित करने की सक्षमता है। नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के नेटवर्क में professionally managed 16 कैम्पस हैं। फैशन एजुकेशन, रिसर्च और डिवलपमेंट, प्रशिक्षण तथा कंसल्टेंसी के क्षेत्रों में परफॉर्मेंस और प्रोसेस की बेंचमार्किंग में यह संस्थान अहम भूमिका निभा रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में हमने देश के अपने-अपने संबंधित राज्यों के बीच निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने हेतु एक healthy competition देखा है। इसके परिणामस्वरूप, राज्यों द्वारा कुछ बड़े सुधार किए गए हैं। अपने-अपने स्तर पर प्रत्येक राज्य ने textiles सहित नए उद्योग स्थापित करने में सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया है। मेरे विचार में, textile का बड़े पैमाने पर निर्यात करने की दिशा में और अधिक ज्यादा ध्यान दिए जाने का वक्त आ गया है।

भारत में अलग-अलग संस्कृति, फैशन और परंपराएं हैं। हमारी यह विविधता विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध कपड़ों में साफ-साफ दिखाई पड़ती है। हमें अपनी clothing diversity को catalogue और map करना चाहिए तथा राज्य या क्षेत्र की strengths और specialties को स्पष्ट रूप से earmark करना चाहिए। प्रत्येक राज्य को कुछ जाने-माने उत्पादों के लिए समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त करने चाहिए, जो पूर्ण वैल्यू चेन में उत्पादकों और व्यापारियों को सहायता प्रदान करेंगे। यह पहल garments के उत्पादन से लेकर निर्यात तक की जानी चाहिए। घरेलू बाजार तथा एक्सपोर्ट मार्किटों की विशेष मांगों की पूर्ति की सुनिश्चिता की जानी चाहिए।

बड़े वैश्विक बाजारों में लोगों की जरूरतों का अध्ययन और मैपिंग करने के लिए हमें एक कार्य योजना बनानी चाहिए और रियल टाइम बेसिस के आधार पर इन क्षेत्रों में फैशन और textiles में new trends पर भी नज़र रखनी चाहिए। सरकारी परिषदों और उद्योग निकायों को इस कार्य में आगे आना होगा, जो उद्योग को सहयोग करेंगे। इससे हमें उपरोक्त जरूरतों को पूरा करने में तथा एक्सपोर्ट को और अधिक बढ़ाने में हमारी ऊर्जा को चनेलाइज करने में सहायता मिलेगी।

मित्रों,

ग्रोथ और वेल्थ जनरेट करने के लिए इनोवेशन और रिसर्च नए मंत्र हैं। कपड़ा उद्योग को ग्रोथ हासिल करने तथा नए बाजारों तक पहुंचने के लिए लगातार इनोवेशन और रिसर्च करना होगा। उदाहरण के लिए, विश्व के कुछ भागों में physiques अधिक होगा। इसके लिए हमारे देश में उपयोग किए जा रहे सामान्य आकार की कपड़ा चौड़ाई की तुलना में, ज्यादा चौड़ाई की आवश्यकता महसूस हो सकती है। इसलिए, आपको loom की चौड़ाई बढ़ानी होगी। बांकी जगहों में आवश्यकताएं अलग-अलग हो सकती हैं। एक्सपोर्ट मार्किटों में लीडरशिप हासिल करने हेतु इस प्रकार की गहन attention जरूरी है।

आज, जीरो कार्बन फूटप्रिंट वाले उत्पादों की भारी मांग है। होलिस्टिक लाइफस्टाइल की गूंज हर जगह सुनाई पड़ती है। आर्गनिक डाइ, कपड़ों और फैब्रिक का बाजार बढ़ता जा रहा है। हमारे प्रयास आर्गनिक उत्पादों में इनोवेट करने की दिशा में होने चाहिए।

कपास और जूट के अलावा, देश में केले और बांस फाइबर से बने फैब्रिक्स पहले से विनिर्मित किए जाते रहे हैं। ऐसे उत्पादों के लिए एक niche market है। अतः, अन्य संसाधनों से फैब्रिक्स विकसित करने हेतु हमारी संस्थाओं, जैसे कि नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टिट्यूट्स द्वारा और अधिक रिसर्च किए जाने की जरूरत है।

देवियों और सज्जनों,

हमारे इंटीग्रेटेड textile clusters वैश्विक पर्यावरण और स्वास्थ्य सुरक्षा मानदंडों का पालन करते हैं। कपड़ा क्षेत्र में निवेशों के लिए अपेक्षित बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराए जाने हेतु कपड़ा उत्पादक राज्यों के पास pro-industry नीतियां मौजूद हैं।

मैं मानता हूं कि अगले दो दिनों में आपको कुछ राज्य सरकारों के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा। मंत्रिमंडल के मेरे कुछ साथी भी आपसे बातचीत करेंगे। मुझे विश्वास है कि आपको ये सत्र काफी पसंद और सूचनाप्रद लगेंगे।

मुझे उम्मीद है कि इस event से वैश्विक और भारतीय लीडरों को इस सेक्टर से जुड़ी भारत की उदारवादी नीति, strengths था सेक्टर में अपार अवसरों से खूब होने में सहायता मिलेगी। इससे भारत को उन देशों के साथ, जो भारत में sourcing और investment अवसरों की तलाश में हैं, valued partner बनने में सहायता मिलेगी। मुझे विश्वास है कि इस इवेंट से भारत की inherent potential को साकार करने में काफी सहायता मिलेगी जिससे भारत textile और apparel सोर्सिंग और निवेश का एक व्यापक destination बन सकता है।

देवियों और सज्जनों,

गांधीनगर में तीन दिनों के सफल और उपयोगी सफर के लिए अपनी शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात संपन्न करता हूँ।

मैं आपको भारत में आने, निवेश करने तथा Textiles बनाने के लिए आमंत्रित करता हूँ।

धन्यवाद

\*\*\*

AKT/AK/GBP